दैनिक नव दुनिया, भोपाल
27 MAR 2013

लेखाजोखा | केन्द्रीय योजना आयोग की सचिव ने मुख्य सचिव को वार्षिक योजना की बैठक से पहले लिखा पत्र

# केन्द्र ने नसीहतों के साथ की सूबे की तारीफ

**भोपाल (ब्यूरो)।** केन्द्रीय योजना आयोग ने वर्ष 2013-14 की सालाना योजना पर बैठक होने से पहले प्रदेश की तारीफ नसीहतों के साथ की है। आयोग की सचिव सिन्धु श्री खुल्लर ने मुख्य सचिव आर परशुराम को पत्र लिखकर जहां 11वीं पंचवर्षीय योजना में विकासदर और टैक्स संग्रहण में वृद्धि पर सूबे की सराहना की है तो चौदह ऐसे क्षेत्र भी गिना दिए जहां सुधार की भरपूर गुंजाइश है। प्रदेश अब आयोग के इस पत्र का जवाब तथ्यों के आधार पर देने की दमदार तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि आयोग की बैठक के पहले हर हाल में जवाब भेज दिया जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक मुख्य सचिव को लिखे पत्र में आयोग की सचिव ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में देश और प्लान से

- 11वीं पंचवर्षीय योजना में विकासदर और टैक्स संग्रहण बढ़ाने पर की सराहना

ज्यादा विकासदर (9.4 प्रतिशत) रहने पर खुशी जाहिर की है। साथ ही टैक्स संग्रहण 8.55 पहुंचने और देनेदारियों में कमी आने पर भी संतोष जाहिर किया है। लेकिन, कृषि के लिए उपलब्ध रकबे का समुचित उपयोग नहीं होने, सिंचाई सुविधा कम होने, पदों के खाली रहने पर चिंता जाहिर की है।

आयोग ने स्कूल में नामांकन में कमी और शिक्षकों के अप्रशिक्षित होने का मुद्दा उठाया है। बर्थरेट, डेथ रेट और आईएमआर देश के औसत से ज्यादा है। 186 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डॉक्टर विहीन हैं। 98 सब सेंटर एएनएम ही नहीं है। कुपोषण चिंता का सबब बना हुआ है। प्रदेश के 30 जिले इस मामले में संवेदनशील हैं। 0 से 6 वर्ष के आयु समूह में लिंगानुपात चिंता के स्तर पर है। केवल 71 प्रतिशत बसाहटों तक पेयजल की सुविधा है। जबकि, राष्ट्रीय औसत 76 फीसदी पहुंच गया है। पाइप वॉटर पानी सप्लाई मात्र 11 प्रतिशत है। 30 फीसदी सतही जल स्त्रोत का सिंचाई में उपयोग हो रहा है। जो कभी 62 फीसदी था। मात्र नौ प्रतिशत ग्राम पंचायतें ही निर्मल हो सकी हैं। 31.2 प्रतिशत बीपीएल परिवारों के पास बिजली के कनेक्शन ही नहीं हैं। इन्हें राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना से कव्हर किया जाए। इसके अलावा आयोग ने अधोसंरचना विकास के कामों में निजी क्षेत्र को जोड़ने पर जोर दिया है। आयोग ने उम्मीद जताई है कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) में इन सभी मुद्दों पर प्रदेश फोकस करेगा। सूत्रों का कहना है कि केन्द्रीय योजना आयोग ने जो मुद्दे उठाए हैं उनमें अधिकांश को प्रदेश की बारहवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जा चुका है। इसके लिए बनाई गई रणनीति का खुलासा वार्षिक योजना पर आयोग में होने वाली बैठक से पहले भेजे जाने वाले डाक्यूमेंट में किया जाएगा।

साथ ही आयोग को पत्र लिखकर भी प्रदेश की ओर से उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताया जाएगा। इसके लिए सभी विभागों से तथ्यात्मक ब्यौरा मांगा गया है।

## सकारात्मक रुख

राष्ट्रीय विकास परिषद के साथ अलग-अलग मंचों से प्रदेश की ओर से उठाई गई मांगों पर आयोग ने सकारात्मक रुख भी दिखाया है। आयोग की सचिव ने पत्र लिखकर कहा है कि सिंगरौली को इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान में शामिल कर गया है। बरगी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए प्रस्ताव जल संसाधन मंत्रालय को भेजा गया है। इंदिरा आवास की लागत दर में इजाफा कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रधानमंत्री सड़क से जुड़े मुद्दों को बारहवीं पंचवर्षीय योजना में लिया जाएगा।